that the negotiations have come to a difficult and a delicate stage. The House must be taken into confidence.

मंत्री महोदय ने कहा है कि सीधा-सादा और घनिष्ट सम्बन्ध उसका हिन्दुस्तान के साथ है और वह हिन्दुस्तान का एक इंटेग्रल पार्ट है। मैं जानना चाहता हूं कि यह वार्ता कितने दिन तक चलेगी और सीज़ फायर को कितने दिन तक इस तरह से लम्बा खींचा जायेगा।

MR. SPEAKER : He has already said that he is not connected with the talks.

SHRI Y. B. CHAVAN : I have nothing to answer.

SHRI BALRAJ MADHOK : He does not need your protection, Sir. He is stout enough to defend himself.

MR. SPEAKER : I am only repeating what he has said. He has clearly said that he does not know at what stage the talks are.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : If he evades the question like this, no negotiations would be successful.

SHRI Y. B. CHAVAN : I am not given to evade any question. I am not in touch with the details of the negotiations. I will not be able to say anything in that regard.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : गाहे-बगाहे अखबारों में चर्चा होती रहती है कि नागालैंड से कुछ लोग पाकिस्तान चले गये या चीन चले गये या पाकिस्तान से वापिस आ गये या चीन से वापस आ गये। कभी-कभी अखबारों की खबरों के आधार पर सवाल भी पूछे जाते हैं। तब गृह मंत्री महोदय भी कह देते हैं कि यह बात सच है। जब इस बात की जानकारी गृह मंत्री महोदय को या उनके विभाग को हो जाती है या इस तरह की चीज़ अखबारों में आ जाती है तो जानकारी मिलने के पहले तहकीकात क्यों नहीं की जाती है उन लोगों को जो कि चीन या पाकिस्तान जा रहे होते हैं पहले ही क्यों नहीं पकड़ लिया जाता है या जब वे वापिस आ रहे होते हैं उनके खिलाफ उचित कारवाई क्यों नहीं की जाती है। समझ में नहीं आता है कि किस तरह से अखबारों में पहिले खबर छप जाती है। इसका मतलब तो यह हुआ कि गृह मंत्री या उनके विभाग से अखबारवाले ज्यादा नज़दीक उनके हैं और उनको ये खबरें आसानी से मिल जाती हैं। मैं जानना चाहती हूं कि इस सब का सबब क्या है ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Naturally, the hon. Member has a right to know. I would try to explain but I do not know how far it will satisfy her. There is no question of anybody giving any information to the press from the Home Ministry as such. Sometimes, the information also emanates from the area itself. These people who go there, naturally, go there in some sort of a secret way, not that they go with any publicity, etc. Even their activities do not remain secret here. I can only claim the credit of knowing their secret activities. But, naturally, we know sometimes after they do it. And these secret things are not secret to the local people. Sometimes, the things leak out from there also. In recent times, no big organised group from Nagaland has been able to go to East Pakistan. That is one thing that I must say. But I am told that some secret contacts have been established with the Chinese, particularly, through the Burmese area, etc. That fact is there. But this is a thing which a very few people secretly do. It is difficult to prevent it. Certainly, we take steps to see that we can prevent it.

NEW DELHI MUNICIPAL COMMITTEE

\+

*332. SHRI YAJNA DATT SHARMA :
SHRI VASUDEVAN NAIR :
SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether leaders of different political parties in the capital have voiced their demand for direct election to the New Delhi Municipal Committee;

(b) whether this demand has been considered by Government; and

(c) if so, the decision taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) It is not proposed to make any change in the present arrangement.

श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या मंत्री महोदय को पता है कि जनसंघ को राजधानी के अन्दर 33 प्रतिशत मत इस बार प्राप्त हुए हैं और जनसंघ के मैट्रोपोलिटन काउंसिलर्ज ने कुछ सिफारिशें इस नगरपालिका की सदस्यता के बारे में कई बार की हैं जिन को सरकार ने सर्वथा अमान्य किया है; इस सारी स्थिति के अन्दर जनसंघ का कोई प्रतिनिधि इस नगरपालिका के अन्दर अभी तक नहीं लिया गया है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह बतायें कि इस नगरपालिका के लिये सदस्यों को मनोनीत करने की यह जो पद्धति है यह केवल जन प्रतिनिधियों को टालने के लिये और अपने कठपुतली लोगों को वहां पर भरने के लिये अपनाई गई है;

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस तरह की कोई पद्धति नहीं है कि कठपुतली लोगों को वहां भेज दिया जाये । नई दिल्ली नगरपालिका को क्यों नामिनेटिड रखा गया है, इसके बारे में कई बार बहस हुई है । इसके कारण भी दिये जा चुके हैं । जहां तक सदस्य महोदय के इस कथन का सम्बन्ध है कि जनसंघ का मैट्रोपोलिटन काउंसिल में बहुमत होते हुए भी उनको यहां पर इस में क्यों नहीं लिया गया है, मैं बतलाना चाहता हूं कि जो सदस्य नामिनेट किये गये हैं वे उपराज्यपाल द्वारा किये गये हैं । उन्होंने हर बात को सोचा विचारा । उनके सामने सब तरह की बातें रखी गई थीं । हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उनके पास गये थे । जो दूसरी संस्थाएं हैं उन सब की बातों को सुन कर उन्होंने नामिनेशन किये । यदि इससे माननीय सदस्य को असन्तोष हो तो उसके बारे में वे उपराज्यपाल महोदय से निवेदन कर सकते हैं और वहीं उनको ऐसा करना भी चाहिये ।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैं यही जानना चाहता हूं कि चुनाव क्यों नहीं कराया जाता है । अलग से राज्यपाल के साथ बैठ कर लोग डिसकस कर लें और वहीं पर चीज़ तय हो जाये यह तो डेमोक्रेटिक पद्धति नहीं है । मैट्रोपोलिटन काउंसिल के लिये चुनाव होता है इस पालिका के लिये भी क्यों न हो? उपराज्यपाल के पास बैठकर उनको कनविस किया जाये और वे जन प्रतिनिधियों को मनोनीत करें यह पद्धति तो अच्छी पद्धति नहीं है, प्रजातांत्रिक पद्धति नहीं है ।

MR. SPEAKER : Please point out which portion of the question he has not answered.

श्री यज्ञदत्त शर्मा : चुनाव किन कारणों से नहीं करवाये जाते हैं;

MR. SPEAKER : He has answered that.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have already answered. If the hon. Member wants, I shall repeat that.

चुनाव किन कारणों से नहीं करवाये जाते हैं, ये सब कारण जब यहां पर पन्त जी गृह मंत्री थे, उन्होंने बताये थे । नन्दा जी ने भी बताये थे । कारण यह है कि यहां पर 85 प्रतिशत से अधिक सरकारी कर्मचारी लोग रहते हैं । सरकार भवन भी यहां बहुत ज्यादा हैं । विदेशी दूतावास भी बहुत-से हैं । इस तरह से नई दिल्ली की एक विशेष परिस्थिति है । यह एक छोटा-सा इलाका है । इस वास्ते यह तय किया गया है कि यहां पर कोई चुनाव न किये जायें । चुनाव कराने के बाद बहुत-सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती थीं जिन से कि यहां का काम चलाने में बड़ी असुविधा होती । इस वास्ते चुनाव न कराने का निर्णय किया गया है और इस पद्धित को बदलने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : सरकारी कर्मचारी पार्लिमेंट के लिये मतदान कर सकते हैं, क्या

पालिका के लिये मतदान नहीं कर सकते हैं ? पालिका के लिये मतदान करने में क्या वे अयोग्य हो जाते हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : अयोग्यता का सवाल नहीं है ।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : आप कह रहे हैं कि सरकारी बस्तियां हैं, सरकारी कर्मचारी बसते हैं । जब सरकारी कर्मचारी पार्लिमेंट के लिये वोट देने का अधिकार रखते हैं और दे रहे हैं और सारे आफिसेस यहां पर हैं तो नगरपालिका के लिये वोट देने के रास्ते में क्या अड़चन पैदा होती है ;

श्री विद्या चरण शुक्ल : यदि माननीय सदस्य धैर्यपूर्वक सुनें तो मैं उनको इसका उत्तर दे सकता हूं । मैंने यह कहा है कि अयोग्यता का सवाल नहीं है । इस नगरपालिका की विशेष परिस्थिति के कारण यह तय किया गया है कि चुनाव नहीं कराया जाना चाहिये । योग्यता और अयोग्यता का प्रश्न नहीं है ।

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : नई दिल्ली नगरपालिका कोई विधायिका के रूप में काम नहीं करती है । उसका काम केवल नाली, पानी आदि नागरिक सुविधायें प्रदान करना है । छोटे-छोटे कसबों और शहरों में जब आप ने नगरपालिकाओं को स्वायत्त संस्थायें बनाया है और उनको उसके अधिकार दिये हैं तो नई दिल्ली के सुशिक्षित और सभ्य समाज के लोगों के ऊपर आपको क्यों सन्देह है; अंग्रेजी राज से चली आ रही एक मांग को कि प्रजातंत्रीय पद्धति इस नगरपालिका के लिए तय की जानी चाहिये, आप को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है;

जो मेम्बर आपने इस पालिका के लिये चने वे सब प्रतिष्ठित नागरिक हैं लेकिन उनके ऊपर आपने प्रेजिडेंट एक ऐसा आदमी बिठा दिया है और बिठा देते हैं जो कि सरकारी आदमी होता है । यह कितनी बड़ी असंगति है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करें ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : क्यों ऐसा करते हैं इसका कारण मैंने बता दिया है । जिस तरह के लोग यहां पर रहते हैं उसे देखते हुए यह जो चुनाव की पद्धति बनाई गई है, इसी को उपयुक्त समझा गया है । किन कारणों से इस पद्धति को अपनाया गया है, यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन कारणों को दोहरा सकता हूं ।

श्री जार्ज फरनेंडीज : न सिर्फ भाषा के बारे में बल्कि स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के बारे में भी कांग्रेस शासन अंग्रेजी शासन का वारिसदार बन कर बैठा है । जैसा नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी का मामला चलता है उसी किस्म का मामला हिन्दुस्तान में कंटोनमेंट्स के बारे में भी चलाया जाता है । कई कम्पनी शहर भी हिन्दुस्तान में चलते हैं । आपने नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के बारे में कई कारण बताये हैं । मैं उन कारणों को समझ सकता हूं लेकिन मानता नहीं हूं । लेकिन आप देखें कि स्वयं इंग्लिस्तान में भी कंटोनमेंट्स में स्थानिक स्वराज्य लोगों को दिया गया है । एक तो यह हिन्दी हिन्दुस्तान में जो अंग्रेजी की चलाई हुई परम्परा है इस परम्परा को कब आप खत्म करेंगे और कैंटोनमेंट के लोगों को स्थानिक स्वराज्य का तमाम अधिकार आप कब देंगे क्योंकि वहां के लोग और वहां काम करने वाले कर्मचारी आप के यह अंग्रेजी-विरासतदारी चलाने से बहुत परेशान हैं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं वह सच नहीं है । कैंटोनमेंट की जो कमेटी है उन का चार्ज सुरक्षा मंत्रालय के पास है, हम लोगों से उस का कोई मतलब नहीं है ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नों का जवाब ठीक नहीं देते हैं ।

श्री जार्ज फरनेंडीज : कम्पनी शहरों का जवाब दीजिये ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने कहा कि यह जो प्रश्न हैं इनसे गृह मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री मधु लिमये : सरकार का सम्बन्ध है या नहीं ; तो कोई न कोई जवाब दें । .....

श्री विद्या चरण शुक्ल : प्रश्नों के समय जिस मंत्रालय से प्रश्न किया जाता है अपने अधिकार की बातों का जवाब वह देता है । इसका मतलब यह नहीं कि सरकार की तरफ से खड़े हों तो वे पूरे सरकार के प्रश्नों का जवाब दें ।

SHRI M. L. SONDHI : Is the hon. Minister aware that there are important plans which Government have, as, for example, the development of tourism etc. and they also want to implement other policies? What is required in New Delhi is a co-operative attitude. But since the NDMC is not responsible, it has, in fact, adopted an intransigent attitude and is engaged in a lot of quarrels with the traders and other private bodies here. I would crave your indulgence to submit that the hon. Minister in charge of tourism had written to me that he could not intervene in a certain matter because the NDMC and the traders were fighting with each other. May I know whether this is within the knowledge of the hon. Minister?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I agree with the hon. Member that a co-operative attitude is necessary, and we find that the NDMC is acting in an attitude of co-operation with various agencies. It is precisely to avoid this kind of quarrels that we have kept it as a nominated body so that the work could go on smoothly in this particular small area.

As far as the quarrel with the traders is concerned, it is not a quarrel over civic amenities, but it is a quarrel about taxes; the traders do not want to pay the amount of tax that the NDMC has assessed on them.

SHRI A. B. VAJPAYEE : No taxation without representation.

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि 85 प्रतिशत जो नई दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर गवर्नमेंट एम्प्लाइज रहते हैं क्या जैसे यह प्रश्न करते हैं, निगम बनने पर वह निगम के एलेक्टेड अधिकारी हो सकते हैं और उस रूप में काम कर सकते हैं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी, नहीं ।

SHRI BAL RAJ MADHOK : The total population of New Delhi consists mainly of big officers and a large number of class III and IV employees of the Government of India who live in special colonies made for them. May I know whether it is a fact that the NDMC which is entirely nominated caters mainly to the interests and the needs and amenities of this rich class that constitutes hardly 10 per cent in New Delhi, whereas the colonies of the class IV and class III people are totally neglected and they have been demanding facilities and amenities again and again? I have myself seen those colonies and I find that roads have not been built and bridges have not been provided and so on and they want that they should have their elected representatives in the NDMC so that their grievances also might be heard. Now, they are completely unrepresented and nobody cares for them. That being so, may I know what steps Government are going to take to see that their grievances are also looked into by the NDMC?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The work of the NDMC is not divided on these lines, depending upon the category of Government servants.

SHRI BAL RAJ MADHOK : That is not a fact.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Actually, within the resources available they try to fulfil the civic needs of all the areas. But it may be that in one area or another there might be some deficiencies, but as soon as they are brought to the

notice of the NDMC action is taken to make up those deficiencies.

SHRI D. N. PATODIA : The nominated character of this municipal committee has been justified on two grounds, firstly because most of the people are Government servants and secondly because several Embassies are there. May I know what disadvantages are expected by Government in case this municipal committee is converted into an elected body? May I also know whether Government are aware that in a similar situation in Canberra, the capital of Australia, the municipality is an elected body ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : That is a matter of opinion. In our opinion, the work can best be done by a nominated body in the situation which is prevailing in New Delhi. It is mainly a matter of opinion and we have our arguments why we should have it like that. The hon. Member may disagree with that opinion.

SHRI D. N. PATODIA : My question was : in what respect does he expect that this body will deteriorate if it becomes elected? What is the difficulty?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : It is a question of opinion. We think that the working of the civic body will not be as efficient as it is if it were elected.

SHRI VAJPAYEE : We are discussing policy or opinion?

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : It is not a question of opinion. He wanted to know how under an elected body, the administration will deteriorate.

MR. SPEAKER : He does not agree with it. That is his opinion. Hon. Members may not agree with it.

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय को यह मालूम है कि लोकल गवर्नमेंट का मुहकमा ट्रांसफर्ड सबजेक्ट है और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन उसको डील करता है और दिल्ली के चीफ एग्जीक्यूटिव कौंसिलर ने एन० डी० एम० सी० के नामिनेशन के लिये कुछ नाम सरकार को दिये कि वह लोग नामिनेट होने चाहियें ; मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे भी बातचीत करने के बाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव कौंसिलर ने लिस्ट दी उसको गृह मंत्री ने यह कहा कि यह ठीक नहीं, तुम्हें यही करना होगा जो दूसरी उन्होंने एक लिस्ट दी ? गवर्नर को एक दूसरी लिस्ट दी और कहा कि तुम्हें यही करना होगा, क्या यह बात ठीक है ? अगर ठीक है तो क्या दिल्ली के ट्रांसफर्ड सबजैक्ट्स के बारे में गृह मंत्रालय इसी तरह से व्यवहार करेगा और क्यों करेगा ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : The hon. Member has asked a very angry question. But I can say he is completely misinformed about this matter. Even in the case of transferred subjects, particularly about nomination of members, the Lt. Governor has certainly got some reserved rights. I had a discussion with the Chief Executive Councillor and there was some understanding. Naturally I could not accept all the recommendations he made.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : You dictated.

SHRI Y. B. CHAVAN : If making suggestion means dictation, I do not know how talks between two friends can be conducted. There was certainly discussion and some differences of opinion; I do not deny it.

The hon. Member was wanting to know what would happen if it were an elected body. This is exactly what is likely to happen, because politics will be introduced in it.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Politics will be there. If that is the argument there, scrap the Metropolitan Council, scrap Parliament.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Only Congress politics is there.

MR. SPEAKER : Order, order.

श्री हरदयाल देवगुण : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया

है कि वहां के रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को वह सुविधायें प्राप्त नहीं होंगी यदि वहां पर चुनाव के जरिये से नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी बने तो इसका अर्थ क्या यह है कि लोकतंत्र के द्वारा जो चुनी हुई संस्था है उससे जनता की सेवा नहीं होती और क्या उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है ? जो वह यहां पर नौकरशाही स्थापित रखने में विश्वास करते हैं कि नौकरशाही से लोकतंत्र की अपेक्षा लोगों की अच्छी सेवा होती है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने यह नहीं कहा कि सरकारी नौकरों को ज्यादा सुविधा देने के लिये इसको नामिनेटिड बाडी रखा गया है । जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि जो पालिटिक्स का एलीमेंट है उसको बाहर रखने के लिये नामिनेटिड बाडी रखा गया है और उसके लिये विशेष परिस्थितियां हैं नई दिल्ली में ।

क्षेत्रीय संगठन

\+

*333. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री० प्र० के देव :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि शिव सेना की तरह की संस्थाएं विभिन्न स्थानों पर संगठित की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रादेशिक भावनाओं को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) and (b). Replies from Governments of Haryana, Gujarat, Orissa, Nagaland, Punjab, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh indicate that there is no organisation on the pattern of Shiv Sena in these States. There is no such organisation in any Union Territory. Replies from remaining State Governments are awaited.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्रीमन्, क्या गृह मंत्री महोदय को यह मालूम है कि शिव सेना की देखा-देखी .....

MR. SPEAKER : Only day before yesterday we discussed it here. If he wishes to waste time and lose time on other questions, he might go ahead. But let him bear this in mind.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : तो उसी तरीके से क्षेत्रीय भावनाओं से लाभ उठाने के लिये नागपुर में नाग सेना, आसाम में लचट सेना और मद्रास में तामिल सेना इस तरह की सेनाओं के संगठन किये जा रहे हैं और उनके पीछे केवल यही भावना है कि राजनीतिक उद्देश्य उनसे पूरे किये जायें ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Naturally, while replying to these questions I have to depend upon the information I get from the States. I have not got a reply from the other States, but certainly I have also information from my reading of the newspapers that these institutions are being mentioned in the press.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या पिछले एलेक्शन में बम्बई से स्वर्गीय मिस्टर बर्वे और उनके पीछे श्रीमती सप्रे और दूसरे कांग्रेसी उम्मीदवारों के एलेक्शन में शिव सेना ने सक्रिय सहयोग कांग्रेस के लोगों को दिया और इसी कारण वहां के कांग्रेस संगठन और सरकार इस शिव सेना के संगठन को समर्थन दे रही है ? इसमें कहां तक सच्चाई है ? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ।

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not know the details about the elections of Mr. Barve and Mrs. Supre, but I have information because I have discussed this matter and I have correspondence with the State